तैयार की थी। योजना के तहत केवल तीन वर्षों के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव था।

(ख) कार्यान्वयन के दौरान कुछ भूलों के कारण, कुछ कृषि सेवा केन्द्रों को पांच वर्षों के लिए अनुदान दिया गया। इस गलती का पता लगाया गया था और राज्य कृषि उद्योग निगमों को अधिक भुगतान की वसूली के लिए अनुदेश दिए गए थे। । कृषि उद्योग निगमों के लिए निर्मुक्त की जाने वाली धनराशि में से कटौती कर के पहले ही वसूलियां की गई हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) को दृष्टिगत रखते हुए, किसी कृषि सेवा केन्द्र को पांच वर्षों के लिए अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त, 1979 में संसाधनों सहित कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इस योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है।

(घ) जी नहीं। केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि औसतन लगभग 75 प्रतिशत केन्द्र लाभ पर चल रहे हैं और किसानों को उपयोगी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उदयमकर्त्ताओं को स्व-रोजगार और अन्य व्यक्तियों को रोजगार तथा किसानों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यों को पर्याप्त तौर पर प्राप्त कर लिया गया है। इस समय लगभग 2900 कृषि सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

Jhuggi Colony behind Maurya Hotel

3797. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a thousand-odd residents of the Juggi colony behind Maurya Hotel have become homeless after a fire completely destroyed their little colony;

(b) if so, the details;

(c) whether any financial help was extended by the Government to these poor people; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) and (b). The Additional District Magistrate, Delhi has reported that about 200 jhuggis were burnt in a fire on 10-11-80 rendering the residents temporarily homeless.

(c) Yes, Sir.

(d) Government sanctioned immediate ex-gratia relief at the rate of Rs. 200 per affetced family.

Constitution of All India Sugar and Sugar cane Board

3798. SHRI BALESAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any demand from the Indian Sugarcane Development Council that a top level decision-making body called "All India Sugar and Sugarcane Board" or "National Sugar Authority" be set up, with full responsibility of taking an overall view of the sugar problem; and

(b) if so, whether Government propose to form such a body and what would be its composition and scope of activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION

(SHRI R. V. SWANITHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government of India.

इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज

3799. **श्री जगदीश सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में भारत के हित में इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज द्वारा अध्ययन किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज से कोई नया प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चौहान) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उसके स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज द्वारा किये जा रहे या किये जाने वाले विश्व के अन्य हिस्सों से सम्बन्धित अधिकतर अध्ययन हमारे देश के हित में हैं क्योंकि उन से उन देशों द्वारा उनके सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने तथा विकास की समझने में मदद मिलेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Exploration and exploitation of ground water

3800. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a plan for exploration and exploitation of ground water;

(b) whether Government are considering to set up a Corporation for the purpose; and

(c) if so, what other steps are being contemplated by Government to supplement the present efforts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a) The Central Ground Water Board is the apex agency at the national level in respect of matters relating to ground water exploration, assessment, scientific management and regulation of country's groundwater resources. It carries out nation-wide systematic survey of groundwater resources. The Board undertakes regional hydrogeological surveys and exploratory drilling in various parts of the country on a macro-level basis to assess the groundwater potential. Under Regional Hydrogeological Surveys the Board has so far covered an area of 16.10 lakh sq. kms. out of the coverable area of 28.70 lakh sq. kms. upto March, 1980. About 4,000 bore-holes have also been drilled

During the Plan period 1980—85, an additional area of 6.60 lakh sq. kms. is proposed to be covered under such surveys and survey of the balance area is proposed to be completed by 1990. 2,500 bore-holes are proposed to be drilled during the next plan.

(b) Government are considering a proposal for setting up a Central Ground Water Corporation for undertaking all exploratory drilling work, constructing production tubewells/bore-wells for irrigation, drinking water and industrial use on commercial basis both for Central Govern-